अजय कुमार मित्तल और जी एस संधावालिया के समक्ष, जे जे

देवेंद्र सिंह यादव व अन्य- *याचिकाकर्ता*

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य *उत्तरदाता*

2011 की सी डब्ल्यू पी संख्या 23876

फ़रवरी 26, 2013

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226,22.7-भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894-धारा 4,5 ए, 6-याचिकाकर्ता की भूमि का अधिग्रहण और धारा 4 और 6 के तहत अधिसूचनाएं जारी-धारा 5 ए के अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन-अधिसूचनाओं को रद्द करने के लिए रिट याचिका-याचिका की अनुमति-धारा 6 के तहत अधिसूचना याचिकाकर्ताओं ने खारिज कर दिया।

अभिनिर्धारित किया गया कि अधिनियम की धारा 5-क के अधीन आपत्तियों की सुनवाई के मुद्दे को बार-बार भूमि मालिकों का बहुत ही भौतिक अधिकार माना गया है, जिनकी संपत्ति को कानून के अनुसार अनिवार्य रूप से अधिग्रहित करने की मांग की गई है। प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा पर्याप्त अधिकार को इस आधार पर दरकिनार नहीं किया जा सकता था कि आपत्तियों को सीमा के आधार पर वर्जित किया गया था।

(Para 13)

आगे यह अभिनिर्धारित किया कि हाल ही में, सुरिंदर सिंह बरार और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, 2012 (4) आरसीआर (सिविल) 684 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चंडीगढ़ में आई.टी पार्क के उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण को रद्द करते हुए कहा कि अधिनियम की धारा 5-A (2) के तहत सुनवाई प्रभावी सुनवाई होनी चाहिए, न कि एक खाली औपचारिकता जिसके आधार पर कलेक्टर

को भूमि के संबंध में एक रिपोर्ट बनानी होगी जिसे अधिसूचित किया जाना है और सरकार को अपनी सिफारिशें भेजनी हैं। आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि इस अनिवार्य प्रक्रिया का कोई भी उल्लंघन पूरे अधिग्रहण को खराब कर देगा।

(Para 14)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि इस प्रकार ऊपर निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए कि अनिवार्य प्रक्रिया का पालन किया जाना है और भूमि मालिकों के पर्याप्त अधिकार को छीन लिया जा रहा है, यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थी संख्या 2 ने याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर आपत्तियों को गलत तरीके से खारिज कर दिया क्योंकि अधिनियम की धारा 5-ए के तहत समय वर्जित है। याचिकाकर्ताओं के पर्याप्त अधिकार को छीन लिया गया, जिन्हें अधिकारियों के समक्ष आग्रह करने और उसके समक्ष यह दिखाने का अधिकार था कि उनकी भूमि इस प्रकार अधिसूचित उद्देश्यों के लिए अधिग्रहित नहीं की जानी चाहिए या कोई बेहतर विकल्प था।

(Para 15)

याचिकाकर्ताओं के लिए अधिवक्ता शैलेंद्र जैन /

Dr. Deepak Jindal, DAG, Haryana.

जी एस संधावालिया, जे.

(1) वर्तमान सिविल रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत दायर की गई है, जिसमें भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894

(संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 4 और 6 के तहत दिनांक 10.01.2011 और 11.05.2011 को जारी अधिसूचनाओं को चुनौती दी गई है।

(2) याचिकाकर्ताओं का अनुरोधित मामला, जिनकी संख्या 22 है, यह है कि वे संलग्न राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार धारूहेड़ा गांव, तहसील और जिला रेवाड़ी में स्थित 227 कनाल और 9 मरले की भूमि के मालिक हैं। भूमि का एक हिस्सा राव शमशेर सिंह के स्वामित्व में था, जो अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना से पहले उक्त भूमि के कुछ हिस्से के मालिक थे और जिनकी मृत्यु 12.02.2011 को हुई थी। इस प्रकार वर्तमान याचिका उनके कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा दायर की जा रही है, अर्थात् याचिकाकर्ता संख्या 1 से 7, जिन्हें प्राकृतिक उत्तराधिकार द्वारा विरासत में मिला है, 10.01.2011 की अधिसूचना धारूहेड़ा शहर में 30 एकड़ 6 कनाल 17 मरला भूमि के अधिग्रहण के लिए नहर आधारित जल कार्यों के निर्माण के सार्वजनिक उद्देश्य के लिए जारी की गई थी। यह अधिसूचना 15.01.2011 को समाचार पत्रों में मेल टुडे (अंग्रेजी) और आज समाज में प्रकाशित की गई थी (Hindi). उक्त समाचार पत्रों का या तो उस शहर में कोई प्रसार नहीं था या न्यूनतम प्रसार था जहां अधिसूचित भूमि स्थित थी। मेसर्स शर्मा न्यूज एजेंसी, धारूहेड़ा द्वारा जारी प्रमाण पत्र को यह दलील देने के लिए संलग्न किया गया था कि मेल टुडे का 0% प्रसार है, जबकि आज समाज ने 20 प्रतियां बेची थीं, जिन्हें खुदरा बिक्री के लिए काउंटर पर रखा गया था, जिनमें से औसतन 8 से 10 प्रतियां प्रतिदिन बेची जाती थीं। इससे पहले, बिक्री सभी हिंदी समाचार पत्रों के 1% (0.57%) से कम थी। याचिकाकर्ता संख्या 1 से 7 ने 04.03.2011 को आपत्तियां दायर की थीं, याचिकाकर्ता संख्या 8 और 9 ने 25.02.2011 को आपत्तियां दायर की थीं, जबकि याचिकाकर्ता संख्या 10 से 23 ने 01.03.2011 को अपनी आपत्तियां दायर की थीं। यह आरोप लगाया गया था कि उक्त आपत्तियों में याचिकाकर्ताओं ने दलील दी है कि भूमि अंतिम विकास योजना दिनांक 14.12.2007 (अनुलग्नक पी-2) के अनुसार वाणिज्यिक भूमि उपयोग क्षेत्र के अंतर्गत आती है और अधिग्रहित किया गया क्षेत्र उक्त सार्वजनिक प्रयोजन के लिए कुल अपेक्षित भूमि से कहीं अधिक था। पंचायत/नगरपालिका से संबंधित 22 एकड़ से अधिक खाली भूमि याचिकाकर्ताओं की भूमि से केवल 800 मीटर दक्षिण में उपलब्ध थी, जिसका कम आर्थिक मूल्य था और उक्त उद्देश्य के

लिए इसका अच्छी तरह से उपयोग किया जा सकता था। तदनुसार यह अनुरोध किया गया कि याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया क्योंकि याचिकाकर्ताओं को प्रतिवादी संख्या 2 से सुनवाई के लिए नोटिस नहीं मिला था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना मांगी गई थी और प्रतिवादी संख्या 2 ने दिनांक 03.08.2011 के पत्र में कहा था कि चूंकि आपत्तियां सीमा से परे प्राप्त की गई थीं, इसलिए व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था।

(3)उत्तरदाता संख्या 1 से 3 की ओर से दायर जवाब में, उत्तरदाताओं द्वारा लिया गया बचाव यह था कि धारुहेड़ा शहर में 1 लाख से अधिक लोगों की आबादी है और यह एक आगामी औद्योगिक केंद्र है और राजस्थान राज्य से सटे दक्षिणी राज्य हरियाणा में स्थित है। यह शहर पीने के पानी की पुरानी कमी से जूझ रहा था और उपरोक्त शहर और आसपास के क्षेत्र के निवासियों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए, नहर आधारित जल कार्यों के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण करने की योजना प्रस्तावित की गई थी। निर्माण बड़े पैमाने पर जनता के लाभ के लिए था और उत्तरदाताओं की कार्रवाई न तो मनमाना, अवैध, अन्यायपूर्ण या क़ानून के अधिकार से परे थी। यह संयंत्र अगले 30 वर्षों तक पीने के पानी की आपूर्ति की आवश्यकता को पूरा करेगा और इसका उद्देश्य पीने के पानी की आपूर्ति की आवश्यकता को पूरा करना है। यह भी कहा गया कि केवल 4 ट्यूबवेल थे और पानी की गुणवत्ता दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। ट्यूबवेल का पानी निकट भविष्य में मानव उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं रहेगा। एक प्रतिवाद यह भी किया गया कि यदि इस भूमि का कब्जा नहर आधारित जलापूर्ति योजना के निर्माण के लिए नहीं दिया जाता है तो सरकार को भी भारी नुकसान होगा क्योंकि विभिन्न आकारों के डक्टाइल लोहे के पाइप खरीदे गए थे और मुआवजे के भुगतान के लिए भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के पास 18 करोड़ रुपये की राशि जमा की गई थी, यह क्षेत्र साबी नदी से सटा हुआ था और जल कार्यों के लिए सबसे उपयुक्त था क्योंकि इससे पानी का प्रवाह सुचारू रूप से और बिना किसी भारी लागत के होगा। यह स्वीकार किया गया कि प्रकाशन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 15.01.2011 को मेल टुडे और आज समाज में किया गया था और इसमें कोई प्रक्रियात्मक चूक नहीं थी। अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना आज 11.05.2011 को मेल में, 17.05.2011 को आज समाज में और 18.05.2011 को पायनियर

(अंग्रेजी) में प्रकाशित की गई थी। यह प्रस्तुत किया गया था कि यह गलत था कि याचिकाकर्ताओं को इसका पता नहीं चल सका और इसलिए वे अधिनियम की धारा 5-ए के तहत समय के भीतर आपत्तियां दायर नहीं कर सके। उन्होंने सीमा अवधि समाप्त होने के बाद आपत्तियां दायर की थीं और उन्हें कानून के अनुसार खारिज कर दिया गया था।

(3) प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से दायर जवाब में, उपरोक्त याचिकाओं के अलावा, यह भी अनुरोध किया गया था कि याचिकाकर्ताओं ने कभी भी आपत्तियां दायर नहीं की थीं और उन्हें तत्काल रिट याचिका में उन आधारों को आंदोलन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह भी आरोप लगाया गया कि समाचार पत्रों के प्रसार के संबंध में प्रमाण पत्र का कोई मूल्य नहीं है और यह न तो साबित हुआ और न ही साक्ष्य में स्वीकार्य था क्योंकि एजेंसी को सरकार द्वारा ऐसा निष्कर्ष निकालने के लिए अधिकृत नहीं किया गया था जैसा कि इस पैरा में आरोप लगाया गया है। इसके बाद, यह स्वीकार किया गया है कि याचिकाकर्ताओं ने सीमा अवधि की समाप्ति के बाद आपत्तियां दायर की हैं, इसलिए उन्हें कानून के अनुसार खारिज कर दिया गया था। यह भी अनुरोध किया गया कि समय के भीतर प्राप्त आपत्तियों पर विधिवत विचार किया गया और संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया गया।

(4) प्रतिकृति में, याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी संख्या 2 की सिफारिश रिपोर्ट की रिकॉर्ड प्रति को अनुलग्नक पी-20 के रूप में रखा, जिसमें यह दर्ज किया गया है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर आपत्तियां 25.02.2011,01.03.2011 और 04.03.2011 को प्राप्त हुई थीं। रैपत रोजनामचा संख्या 367 दिनांक 07.02.2011 का भी उल्लेख किया गया था, जिसमें अधिनियम की धारा 4 के तहत ड्रम बजाने (मुनादी) के माध्यम से विवादित अधिसूचना की घोषणा की गई थी। तदनुसार, यह अनुरोध किया गया कि याचिकाकर्ताओं ने उक्त रापत रोजनामचा के प्रवेश के 30 दिनों के भीतर आपत्तियां दायर कीं। यदि 30 दिनों की अवधि को उस इलाके में, जहां भूमि स्थित है, विषय अधिसूचना के सार की

सार्वजनिक सूचना देने से लिया गया था, तो याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर की गई उक्त आपत्तियां पूरी तरह से सीमा के भीतर थीं और चूंकि सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया था, इसलिए पूरी कार्यवाही को अलग कर दिया जाना चाहिए था। आधिकारिक उत्तरदाताओं ने प्रतिकृति के लिए कोई काउंटर दाखिल नहीं करने का फैसला किया, जिसमें ड्रम की धड़कन (मुनादी) के माध्यम से सार्वजनिक सूचना के माध्यम से की जा रही अधिसूचना के सार के अतिरिक्त तथ्य का उल्लेख किया गया था।

(5) उपरोक्त अभिवचनों को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ताओं के वकील ने अपने दावे को सीमित कर दिया है और अधिनियम की धारा 5-ए के तहत आपत्तियों को प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा गलत तरीके से सीमा के आधार पर खारिज किए जाने के आधार पर अधिनियम की धारा 6 के तहत बाद की अधिसूचना पर हमला किया है। याचिकाकर्ता के वकील ने तदनुसार तर्क दिया है कि समाचार पत्रों में प्रकाशन उन समाचार पत्रों में था जो उस क्षेत्र में प्रसारित नहीं हो रहे थे जो मेल टुडे (अंग्रेजी) और आज समाज थे (हिंदी)।

(6) तदनुसार, उस समाचार एजेंसी द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र पर निर्भरता रखी गई जो पिछले 40 वर्षों से धारूहेड़ा में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का एकमात्र वितरक और विक्रेता था। दूसरा, यह आग्रह किया गया था कि अधिनियम की धारा 5-ए के तहत आपत्तियों को इस तथ्य के मद्देनजर सीमित करने के आधार पर खारिज करना टिकाऊ नहीं था कि वे 07.02.2011 को अधिसूचना के सार की तारीख से 30 दिनों के भीतर दायर किए गए थे, जो ड्रम की बीट के माध्यम से था (मुनादी) ।

(7) दूसरी ओर, राज्य के वकील ने इस आधार पर अधिग्रहण का बचाव किया कि आपत्तियां 30 दिनों की अवधि के भीतर दायर की जानी थीं और याचिकाकर्ताओं ने स्वयं दलील दी थी कि उन्होंने 25.02.201101.03.2011 और 04.03.2011 को आपत्तियां दायर की थीं और इस प्रकार प्रस्तुत किया था कि

प्रतिवादी संख्या 2 उन आवेदनों को खारिज करने में उचित था जो समय से वर्जित थे और उन आवेदनों की सूचना जारी करने का कोई सवाल ही नहीं था जो स्पष्ट रूप से 10.01.2011 को अधिसूचना की तारीख और समाचार पत्र में प्रकाशन की तारीख 15.01.2011 से वर्जित थे।

(8) पक्षों के वकील को सुनने पर, हमारी राय है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा ली गई याचिका में सार है और इसे स्वीकार किया जा सकता है। राज्य द्वारा सार्वजनिक उद्देश्य के लिए याचिकाकर्ताओं की भूमि का अधिग्रहण, जिसके पास प्रतिष्ठित क्षेत्र का अधिकार है, विवादित नहीं है। हालांकि, भूमि के मालिकों को आपत्ति करने और अधिग्रहण करने वाले प्राधिकरण को यह बताने का अधिकार है कि अधिग्रहित की जाने वाली भूमि उस उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं है जिसे वह अधिग्रहित कर रहा है या यह कि इसे विरोधाभास में या किसी योजना या मास्टर प्लान के उल्लंघन में अधिग्रहित किया जा रहा है। इच्छुक व्यक्ति यह भी दिखा सकते हैं कि वैकल्पिक भूमि उपलब्ध है जो खाली पड़ी है जबकि जिस भूमि का अधिग्रहण करने की मांग की गई थी वह उपजाऊ भूमि थी और वे प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगे। अधिनियम की धारा 4 में प्रावधान है कि किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आवश्यक भूमि के लिए एक अधिसूचना जारी की जानी चाहिए जिसे उस इलाके में प्रसारित होने वाले आधिकारिक राजपत्र और दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाना है। कलेक्टर को सार्वजनिक सूचना और ऐसी अधिसूचनाओं का सार भी देना होगा जो उक्त इलाके में सुविधाजनक स्थानों पर दी जानी है। इस तरह की सार्वजनिक सूचना देने को इस तरह के प्रकाशन की अंतिम तिथि माना जाना है।

(9) पहले मुद्दे के बारे में कि धारा 4 में विशेष रूप से यह प्रावधान

किया गया है कि प्रकाशन उस इलाके में प्रसारित होने वाले दो समाचार पत्रों में होना चाहिए, जिनमें से एक क्षेत्रीय भाषा में होना चाहिए, याचिकाकर्ता काफी हद तक यह प्रदर्शित करने में सक्षम रहे हैं कि अंग्रेजी समाचार पत्र "मेल टुडे" धारहकरा के क्षेत्र में 0% प्रसार था। विशिष्ट आरोपों का खंडन और खंडन करने के अलावा। प्रत्यर्थी-राज्य किसी भी तरह से उक्त आरोप का खंडन करने में सक्षम नहीं रहा है, रिकॉर्ड पर कुछ भी रखते हुए कि मेल टुडे का इलाके में कुछ प्रसार था। इसी तरह, आज समाज नामक समाचार पत्र, जिसमें अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, के बारे में कहा गया है कि इसकी 8 से 10 प्रतियों की बिक्री होती है, जो खुदरा बिक्री में भी प्रतिदिन बिकती हैं और इलाके में प्रसारित नहीं होती हैं, जिससे आम जनता को अधिग्रहण के बारे में जागरूक किया जा सकता है जिससे सीमा को गिना जा सकता है। अधिनियम की धारा 4 (1) के इस तरह के उल्लंघन पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष उप कलेक्टर, भूमि अधिग्रहण सीएम डीए बनाम जे शिवप्रकाशम और अन्य मामलों में चर्चा की गई है (7). उक्त मामले में, उस इलाके में प्रसारित समाचार पत्र की परिभाषा विचार का विषय थी और यह अभिनिर्धारित किया गया था कि इसका उद्देश्य इच्छुक व्यक्तियों को आपत्तियां दायर करने का अवसर देने के लिए पर्याप्त प्रचार सुनिश्चित करना है। तदनुसार यह अभिनिर्धारित किया गया कि संख्या की परवाह किए बिना इलाके की आम जनता के बीच नियमित और त्वरित प्रसार होना चाहिए। संबंधित परिच्छेद निम्नानुसार हैंः -

> *"17. 1984 के संशोधन अधिनियम 68 द्वारा, धारा 4 (1) में संशोधन किया गया था, जिसमें इलाके में प्रसारित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में अधिसूचना के प्रकाशन से संबंधित अतिरिक्त आवश्यकता को शामिल किया गया था। इस तरह के समाचार पत्र प्रकाशन की आवश्यकता का उद्देश्य अधिसूचना को यथासंभव व्यापक प्रचार देना है, क्योंकि राज्य*

राजपत्रों का व्यापक प्रसार नहीं है और इलाके में सुविधाजनक स्थानों पर अधिसूचना के सार के बारे में सार्वजनिक सूचना देना केवल इलाके के विशिष्ट क्षेत्रों में ही सूचना देगा। इसलिए विधायिका ने दो समाचार पत्रों में प्रकाशन का प्रावधान किया, जिनमें से कम से कम एक क्षेत्रीय भाषा में व्यापक पहुंच के लिए हो। प्रावधान के उद्देश्य और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि प्रकाशन उन समाचार पत्रों में होना चाहिए जिनका इलाके में उचित रूप से अच्छा प्रसार हो, प्रकाशन केवल सांकेतिक या महत्वहीन प्रसार वाले अस्पष्ट समाचार पत्रों में किया जाना चाहिए, या तो प्रकाशन की लागत में कटौती करने के लिए या राजनीतिक या आधिकारिक संरक्षण के माध्यम से, जो समाचार पत्रों में प्रकाशन के लिए प्रावधान करने के उद्देश्य को विफल कर देगा।

18. दूसरी ओर, यदि उस इलाके में प्रसारित होने वाले समाचार पत्रों की व्याख्या विशुद्ध रूप से शाब्दिक और सामान्य अर्थों में की जाती है, तो उनका मतलब होगा कि इलाके में आम जनता के बीच नियमित और स्थिर प्रसार वाले समाचार पत्र, चाहे संख्या कुछ भी हो, उस अर्थ में उस इलाके में बेचे जाने वाले क्षेत्रीय समाचार पत्रों के कुल प्रसार आंकड़ों में से 2% से 3% बाजार हिस्सेदारी रखने वाले समाचार पत्र को भी "इलाके में प्रसारित" समाचार पत्र माना जा सकता है। इसलिए, जहां उस इलाके में प्रसारित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्रों (एक जो कम से कम क्षेत्रीय भाषा में होना चाहिए) में तकनीकी या शाब्दिक अर्थों में प्रकाशन से संबंधित आवश्यकता का अनुपालन होता है, लेकिन यह पाया जाता है कि उन समाचार पत्रों का इलाके में बेचे जाने वाले समाचार पत्रों की कुल संख्या का केवल 2% से 3% का प्रसार हिस्सा है, तो पूरे अधिग्रहण को यांत्रिक रूप से अमान्य करना संभव नहीं हो सकता है, इस आधार पर

कि दो क्षेत्रीय समाचार पत्र जिनमें अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, "उस इलाके में प्रसारित" नहीं थे।

19. हमने अभिनिर्धारित किया है कि अधिनियम की संशोधित धारा 4 (च) का उद्देश्य और उद्देश्य दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन का प्रावधान करना है, जो इलाके में यथोचित रूप से व्यापक प्रसार करते हैं ताकि उस इलाके के लोग (इच्छुक व्यक्ति) अधिग्रहण के प्रस्तावों के बारे में जागरूक हो सकें। हमने यह भी माना है कि दो समाचार पत्रों में प्रकाशनों का नियमित और स्थिर प्रसार होता है, लेकिन कुल समाचार पत्रों में से केवल 2% से 3% की बाजार हिस्सेदारी होने से अधिग्रहण की कार्यवाही स्वचालित रूप से अमान्य नहीं हो सकती है, इस आधार पर कि ऐसा प्रकाशन समाचार पत्र प्रकाशन से संबंधित धारा 4 (1) की आवश्यकता का उल्लंघन करता है, उक्त दो निष्कर्ष थोड़े विरोधाभासी हैं, परिणामों को सुसंगत करना आवश्यक है।

(10) वर्तमान मामले में, जैसा कि ऊपर देखा गया है, अंग्रेजी समाचार पत्र मेल टुडे का कोई प्रसार नहीं है, जहां आज समाज ने केवल 8 से 10 प्रतियों की बिक्री की है, जो उक्त शहर के सभी हिंदी समाचार पत्रों के 0.57% से कम है, आधिकारिक उत्तरदाताओं ने उक्त आरोपों का खंडन करने के लिए कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं रखा है और इसलिए, इस अदालत की राय है कि याचिकाकर्ता यह प्रदर्शित करने में सफल रहे हैं कि समाचार पत्रों के खराब प्रसार को देखते हुए जिसमें धारा 4 अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, वे 15.01.2011 से सीमा के भीतर अपनी आपत्तियां दर्ज करने के लिए पूर्वाग्रहित थे।

(11) स्वीकार्य है, वर्तमान मामले में, अधिसूचना का सार 07.02.2011 को रैपट रोजनामचा संख्या 367 के अनुसार ड्रम की बीट के माध्यम से प्रकाशित किया गया था। इस प्रकार अधिनियम की धारा 5-ए के तहत

आपत्तियां दर्ज करने के उद्देश्य से उक्त तिथि से सीमा की गणना की जानी थी, जो अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन है। अधिनियम की धारा 4 (1) निम्नानुसार हैः -

"4. प्रारंभिक अधिसूचना और उस पर अधिकारियों की शक्तियों का प्रकाशनः-जब भी उपयुक्त सरकार को यह प्रतीत होता है कि किसी लोक प्रयोजन के लिए या किसी कंपनी के लिए किसी इलाके में भूमि की आवश्यकता है या इसकी आवश्यकता होने की संभावना है, तो उस आशय की एक अधिसूचना सरकारी राजपत्र में और उस इलाके में प्रसारित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी, जिनमें से कम से कम एक क्षेत्रीय भाषा में होगी, और कलेक्टर ऐसी अधिसूचना के सार की सार्वजनिक सूचना उक्त इलाके में सुविधाजनक स्थानों पर ऐसे प्रकाशन की अंतिम तिथियों और ऐसी सार्वजनिक सूचना देने की सार्वजनिक सूचना देगा, जिसे इसके बाद अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के रूप में संदर्भित किया जाएगा। "

(12) एक बार जब सामग्री को केवल 07.02.2011 को इलाके में प्रकाशित किया गया था, तो याचिकाकर्ता के वकील ने यह तर्क देते हुए उचित ठहराया कि 30 दिनों की सीमा अवधि उस तारीख से शुरू होगी और 06.03.2011 तक जारी रहेगी और याचिकाकर्ता संख्या 8 और 9 द्वारा 25.02.2011 को याचिकाकर्ता संख्या 10 से 22 और 04.03.2011 को याचिकाकर्ता संख्या 1 से 7 द्वारा दायर आपत्तियां सीमा के भीतर थीं और प्रतिवादी संख्या 2 ने 15.01.2011 से सीमा की गणना करके सीमा के आधार पर इसे खारिज करने में त्रुटि की थी, जो समाचार पत्रों में प्रकाशन की तारीख थी।

(13) अधिनियम की धारा 5-क के अधीन आपत्तियों की सुनवाई का मुद्दा बार-बार भूमि मालिकों का बहुत ही भौतिक अधिकार माना गया है, जिनकी संपत्ति को कानून के अनुसार अनिवार्य रूप से अधिग्रहित करने

की मांग की गई है। प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा पर्याप्त अधिकार को इस आधार पर दरकिनार नहीं किया जा सकता था कि आपत्तियों को सीमा के आधार पर वर्जित किया गया था। तीन न्यायाधीश मुंशी सिंह और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने (2) निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित कियाः-"7. धारा 5-ए एक बहुत ही न्यायसंगत और संपूर्ण सिद्धांत का प्रतीक है कि एक व्यक्ति जिसकी संपत्ति अर्जित की जा रही है या जिसका अधिग्रहण करने का इरादा है, उसके पास संबंधित अधिकारियों को यह समझाने का उचित और उचित अवसर होना चाहिए कि उस व्यक्ति की संपत्ति का अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। हम मंडेश्वर प्रसाद और दूसरे बनाम केंद्र शासित प्रदेश राज्य और अन्य, (1964) 3 S.C.R में इस अदालत के अवलोकन का उल्लेख कर सकते हैं। 440, कि धारा 5-क के अधीन आपत्ति दर्ज करने का अधिकार एक महत्वपूर्ण अधिकार है जब किसी व्यक्ति की संपत्ति को अधिग्रहण से खतरा हो रहा है और उस अधिकार को इस प्रकार नहीं लिया जा सकता है जैसे कि एक साइड विंड द्वारा। धारा 5-ए की उपधारा (2) कलेक्टर पर यह अनिवार्य बनाती है कि वह किसी आक्षेपकर्ता को सुनवाई का अवसर दे। सभी आपत्तियों को सुनने और आगे की जांच करने के बाद उन्हें उपयुक्त सरकार को एक रिपोर्ट देनी है, जिसमें आपत्तियों पर उनकी सिफारिश अंतिम है। धारा 5-ए के तहत कलेक्टर द्वारा दी गई रिपोर्ट, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद उपयुक्त सरकार के संतुष्ट होने के बाद धारा 6 के तहत घोषणा की जानी चाहिए।

(14) *इसलिए, विधायिका ने इच्छुक व्यक्तियों के लिए प्रस्तावित अधिग्रहण के खिलाफ आपत्तियां दर्ज करने और अपनी आपत्तियों के निपटान के*

लिए पूर्ण प्रावधान किए हैं। यह केवल तात्कालिकता के मामलों में है कि उपयुक्त सरकार को धारा 5-ए के प्रावधानों को समाप्त करने के लिए विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं: (अधिग्रहण अधिनियम की धारा 17 (4) देखें)

(15) *हाल ही में, सुरिन्दर सिंह बरार और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चंडीगढ़ में आई. टी. पार्क के प्रयोजनों के लिए भूमि अधिग्रहण को निरस्त करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम की धारा 5-ए (2) के अधीन सुनवाई प्रभावी सुनवाई होनी चाहिए न कि एक खाली औपचारिकता जिसके आधार पर कलेक्टर को उस भूमि के संबंध में एक रिपोर्ट बनानी होगी जिसे अधिसूचित किया जाना है और सरकार को अपनी सिफारिशें अग्रेषित करनी हैं। आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि इस अनिवार्य प्रक्रिया का कोई भी उल्लंघन पूरे अधिग्रहण को खराब कर देगा। प्रासंगिक भाग इस प्रकार है: -*

> *"58. इस बात पर जोर दिए जाने की आवश्यकता है कि धारा 5ए (2) के तहत उस व्यक्ति की सुनवाई की जानी चाहिए जिसे उसकी भूमि से वंचित करने की मांग की गई है और जिसने धारा 5ए (1) के तहत आपत्तियां दायर की हैं, वह प्रभावी होनी चाहिए न कि एक खाली औपचारिकता। कलेक्टर, जिसे विरोध करने वालों को सुनने का कार्य सौंपा गया है, को आगे की जांच करने की स्वतंत्रता है जैसा कि वह आवश्यक समझता है। किसी भी स्थिति में, उसे धारा 4 (1) के तहत अधिसूचित भूमि के संबंध में रिपोर्ट बनानी होगी या ऐसी भूमि के विभिन्न भागों के संबंध में आपत्तियों पर अपनी सिफारिशों के साथ उपयुक्त सरकार को अलग-अलग रिपोर्ट देनी होगी और बाद के निर्णय के लिए उसके द्वारा आयोजित कार्यवाही के रिकॉर्ड के साथ उपयुक्त सरकार को प्रस्तुत करनी होगी। उपयुक्त सरकार धारा 5ए (2) के तहत बनाई गई रिपोर्ट, यदि कोई हो, पर विचार करने और फिर अपनी संतुष्टि दर्ज करने के लिए बाध्य है कि विशेष भूमि की सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आवश्यकता*

है। यह अभ्यास एक घोषणा करने में समाप्त होता है कि भूमि एक सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आवश्यक है और घोषणा पर सरकार के सचिव या इसके आदेशों को प्रमाणित करने के लिए विधिवत अधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता और उसकी उपयुक्तता के मुद्दे पर राय का गठन धारा 6 के तहत घोषणा जारी करने के लिए अनिवार्य है।(1). भूमि मालिकों और/या अन्य इच्छुक व्यक्तियों के आपतियां दर्ज करने के मौलिक अधिकार का कोई भी उल्लंघन या आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत सुनवाई के अवसर से इनकार कलेक्टर द्वारा की गई सिफारिशों और ऐसी सिफारिशों पर उपयुक्त सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को दूषित करता है। धारा 5क (1) के अधीन दायर आपत्तियों और धारा 5क (2) के अधीन सुनवाई के दौरान की गई दलीलों पर विधिवत विचार किए बिना कलेक्टर द्वारा की गई सिफारिशें या कलेक्टर द्वारा की गई सिफारिशों के आलोक में ऐसी आपत्तियों पर वस्तुनिष्ठ निर्णय लेने में उपयुक्त सरकार की विफलता, उपयुक्त सरकार के वैधानिक अंतिमता के निर्णय को नकार देगी। दूसरे शब्दों में कहें तो, उपयुक्त सरकार द्वारा दर्ज किया गया संतोष कि विशेष भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है और धारा 6 (1) के तहत की गई घोषणा कानूनी पवित्रता से रहित होगी यदि संबंधित अधिकारियों द्वारा वैधानिक रूप से उत्कीर्ण प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन नहीं किया जाता है या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होता है। हमारे समक्ष मामले धारा 5ए (2) और 6 के अधिदेश के घोर उल्लंघन के उदाहरण हैं(J). अतः प्रश्न संख्या (ii) का उत्तर सकारात्मक दिया जाता है। "

(16) इस प्रकार, ऊपर निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए कि अनिवार्य प्रक्रिया का पालन किया जाना है और भूमि मालिकों के पर्याप्त अधिकार को छीन लिया जा रहा है, यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि वर्तमान मामले में, प्रतिवादी संख्या 2 ने याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर आपत्तियों

को गलत तरीके से खारिज कर दिया क्योंकि अधिनियम की धारा 5-ए के तहत समय वर्जित है। याचिकाकर्ताओं के मूल अधिकार को छीन लिया गया, जिन्हें अधिकारियों के समक्ष आग्रह करने और उसके समक्ष यह दिखाने का अधिकार था कि उनकी भूमि इस प्रकार अधिसूचित उद्देश्यों के लिए अधिग्रहित नहीं की जानी चाहिए या कोई बेहतर विकल्प था।

(17) तदनुसार, हम रिट याचिका की अनुमति देते हैं और याचिकाकर्ताओं को कानून के अनुसार आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र छोड़ते हुए अधिनियम की धारा 6 के तहत जारी 11.05.2011 की अधिसूचना को रद्द कर देते हैं, जैसा कि ऊपर देखा गया है।

ए जैन

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अवीषेक गर्ग

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)
हिसार, हरियाणा